

प्रो. सेन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित छठें भारतीय व्यक्ति है जिन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये यह सम्मान दिया गया। इन्होंने अर्थशास्त्र और इसके दर्शन के संयोजन से महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं और विचार विमर्श को नैतिक आयाम दिया है।

सामाजिक विषमता और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भूमि सुधार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि इस बात का संकेत नहीं देती है कि इससे निरक्षरता, स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक अभावों का समाधान किया जा सकता है।

अमर्त्य सेन का मानना है कि 'भारत में खेतिहर मजदूर खेतों पर अत्यंत परिश्रम करते हैं पर उस अनुपात में उन्हें उत्पादन में कम हिस्सा मिलता है। भूमि सुधार वह महत्वपूर्ण कार्य है जिसके द्वारा गरीबी उन्मूलन, खेतिहर मजदूरों एवं छोटे-छोटे काश्तकारों की समस्या को दूर करके, यह उनके अधिकारों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। बाजार और सरकार की कार्यवाही ऐसी होनी चाहिये कि वह मध्यम मार्ग अपनाए न कि बहुत अधिक हस्तक्षेप की।

भारत में महिलाओं के प्रति खाद्य एवं पालन-पोषण पर उपेक्षित रवैया अपनाया जाता है। लेकिन भारतीय समाज संयुक्त परिवार की जीवन पद्धति पर आधारित है अतः इसे आधुनिक समाज के अनुसार विकसित करना होगा क्योंकि महिलाओं की शिक्षा पर ही सीमित परिवार, पारिवारिक स्वच्छता एवं परिवार का हित निहित है।

लोकतंत्र में विश्वास रखते हुये आपका कहना है कि राजसत्ता को दूरदर्शी दृष्टि अपनानी होगी क्योंकि भारत विविधता में एकता का प्रतीक है और इसी विशेषता के आधार पर हमारे देश ने पृथकतावादी तत्वों को परास्त किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था नागरिकों को स्वतंत्रता देती है कि वह अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें।

अकाल का एकमात्र कारण खाद्यान्न की कमी नहीं बल्कि इस समस्याओं के लिये सामाजिक मूल्य दर्शन, नीतिशास्त्र, सरकार की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक नीतियाँ भी महत्वपूर्ण होती हैं। दो मुख्य तत्व जो अकाल के लिये जिम्मेदार हैं।

1. सरकार द्वारा मुद्रास्फीति के कारण कीमत में तीव्र वृद्धि गरीबों पर बुरा प्रभाव डालती है।
2. सट्टा, जमाखोरी के कारण बाजार-पूर्ति में कमी भी कीमत में तीव्र वृद्धि में सहायक होती है।

अकाल से बचने के लिये लोकतंत्र सबसे अच्छी प्रणाली है क्योंकि विपक्ष और मीडिया के दबाव के परिणाम स्वरूप सरकार समस्या का समाधान करने के लिये बाध्य होती है जबकि निरंकुश प्रणाली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों के लिये सामाजिक व्यवस्था अपनायी जानी चाहिये। डॉ. अमर्त्य सेन ने यह सुझाया कि भारत को समाज के कल्याण मूलक कार्यक्रमों में व्यय करना चाहिए।

सन् 1970 में प्रो. सेन ने **Collective Choice of Social Welfare** नामक पुस्तक में विकास और आय के वितरण पर विचार किया है। सामाजिक विकल्प सिद्धान्त के द्वारा, विकास एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों में लाभ किन वर्गों को मिल रहे हैं, इसका पता लगाया जा सकता है। प्रो. सेन ने 1973 में प्रकाशित अपनी पुस्तक **On Economic in Quality** में गरीबी निर्देशांक बनाने के लिये एक फार्मूला दिया जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की आय में विषमता पर आधारित है।

नोबेल समिति ने सही रूप से अकाल तंत्र पर सेन के विश्लेषण की सराहना की। सेन द्वारा विकसित सामर्थ्य की धारणा में मानवजाति के पर्याप्त एवं पोषक भोजन, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधा एवं सुरक्षा के उपाय सुझाये गये हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था के पूंजीप्रधान तकनीक देश की आर्थिक नींव को मजबूत आधार प्रदान कर सकती है। रोजगार के अवसरों के विस्तार की सीमा, श्रम आधारित परियोजना की अपेक्षा पूंजी आधारित परियोजना में अधिक है।

निष्कर्ष रूप में प्रो. अमर्त्य सेन राजनैतिक दार्शनिक रूप में स्वतंत्रता और मानवता के प्रेमी है। यह समय सामर्थ्यवान को अधिकार देने का है, अतः आवश्यकता है — शिक्षा, स्वास्थ्य पोषण एवं सुरक्षा को देने का। राज्य की भूमिका, सामाजिक क्षेत्र की उपेक्षा के बजाय उसे उत्पादन का साधन बनाने का है।